Minister, it is proposed to withdraw the Essential Commodities (Amendment) Bill, 1998 pending in the Lok Sabha and introduce the revised Essential Commodities (Amendment) Bill, 1999 in the Lok Sabha.

(b) The proposed amendments include substantial increase in fines and imprisonment, making of all offences congnizable and non-bailable except the minor offences committed for the first time, requirement of prior permission of an officer not below the rank of Executive Magistrate for making entry, search and seizure, power of arrest to be exercised by an officer not below the rank of Sub-Inspector of police, sale of seized goods to be sold through PDS, provision for allowance of margin between physical stock and stock in record, appeal against confiscation to lie with the State Government and deletion of the item "component parts and accessories of automobiles" from, the list of essential commodities.

(c) and (d) The amendments aim at providing more deterrent action against hoarders and blackmarketeers.

सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा खाद्यान्नों के वितरण में धांधली

1135. **श्री नरेन्द्र मोहन:** क्या खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किया गया खाद्यान्न लक्षित व्यक्तियों तक पहुंचता है;

(ख) क्या भारत सरकार इस संबंध में किसी प्रकार की धांधली की जानकारी रखती है; और

(ग) वे कौन-कौन से राज्य हैं, जहां से भारत सरकार को सार्वजनिक वितरण प्रणाली में कमियों या खामियों की जानकारी प्राप्त हुई है?

खाद्य और उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सत्य पाल सिंह यादव): (क) जी, हां। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरित किए जाने वाले खाद्यान्न लक्षित उपभोक्ताओं को पहुंचते हैं। किन्तु इन खाद्यान्नों के कुछ विपथन होने की संभावना से बिल्कुल इंकार नहीं किया जा सकता।

(ख) और (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्रियान्वयन केन्द्र और राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी के तहत किया जाता है। केन्द्रीय सरकार चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेल और मिट्टी के तेल जैसी कतिपय आवश्यक वस्तुओं की वसूली करती है और इन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत राजसहायता प्राप्त मूल्यों पर राज्यों को उपलब्ध कराती है और राज्य सरकारें उचित दर दुकानों के नेटवर्क के जरिये इन वस्तुओं को उपभोक्ताओं के बीच वितरित करती हैं।

गर्भपात के मामलों में बढ़ोतरी

1136. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शहरी क्षेत्रों में गर्भपात करवाने के मामलों में निरन्तर बढ़ोतरी हो रही है तथा शिक्षित महिलाएं बालिका शिशु को जन्म देने में और उदासीन हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार बालिका जन्म धारण को सुरक्षित करने तथा उनके गर्भपात किए जाने पर प्रतिबंध लगाने के लिए विधेयक लाने पर विचार कर रही है;

(ग) क्या सरकार ने देश में प्रतिवर्ष हो रहे गर्भपातों की सही संख्या का पता लगाने के लिए कोई प्रयास किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री दलित एजिलम्लाई): (क) जी, हां। चिकित्सीय गर्भ-समापन (एम०टी०पी०) अधिनियम, 1971 के लागू होने के समय से वैध गर्भपातों की संख्या में वृद्धि हो रही है। वैसे, इस बात का कोई प्रमाण नहीं है कि शिक्षित महिलाएं लड़कियों को जन्म देने में उदासीन हो रही हैं।

(ख) चिकित्सीय गर्भ-समापन (एम०टी०पी०) अधिनियम, 1971 और नियम तथा विनियम, 1975 अवैध गर्भपातों को दृढ़ता से निरूत्साहित करते हैं जिनके लिए दण्ड भी निर्धारित किए गए हैं। इस अधिनियम में ऐसी विशिष्ट शर्तें निर्धारित की गई हैं जिनके तहत कतिपय परिस्थितियों में वैध गर्भपातों की अनुमति दी जा सकती है।

प्रसव-पूर्व नैदानिक तकनीक (विनियमन एवं दुरुपयोग निवारण) अधिनियम, 1994 के कार्यान्वयन के माध्यम

से सरकार ने बालिका भ्रूण की सुरक्षा के लिए कदम उठाए हैं।

(ग) और (घ) एम०टी०पी० अधिनियम, 1971 के अधिनियमन से सरकार किए गए गर्भपातों की संख्या का मूल्यांकन करने के लिए अनुमोदित एम०टी०पी० केन्द्रों में चिकित्सीय गर्भ-समापन संबंधी सेवाओं की मानीटरिंग कर रही है। वैसे, अवैध गर्भपातों के कोई पुष्ट आंकड़े नहीं हैं। चिकित्सीय गर्भ-समापन अधिनियम, 1971 और नियम और विनियम, 1975 के कार्यान्वयन के माध्यम से केन्द्र और राज्य सरकारें अवैध गर्भपातों के विरुद्ध उपाय कर रही हैं।

Children not covered under Pulse Polio

1137. SHRIMATI BASANTI SARMA: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned, "10 million children not covered under Pulse Polio", appeared in the Times of India, dated 18th January, 1999;

(b) if so, the details thereof and the reasons therefor; and

(c) what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) Yes, Sir.

(b) While preliminary reports received from the states indicate 100% coverage under Pulse Polio Immunization (PPI) Programme evaluation of the coverage is being conducted annually through an independent agency. The evaluation for the year 1997-98 indicates 92% of coverage of the children below 5 years of age against the target of 126 million children. Thus it is estimated that about 10 million children did not receive both of the polio doses.

(c) A small perventage of children gets missed out during the PPI drive because of inability of the parents to bring their children to the booths. India is determined to achieve zero incidence of polio by 2000. Government in consultation with national and international experts, has decided upon a strategy for intensifying PPI programme by taking some additional measures over and above the holding of two PPIs in December, and January. On March 14, 1999, one additional round of polio immunization will be conducted through out the states of Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh and Rajasthan where infection is still widespread, while in all other states a population of 100,000 surrounding each positive case of polio will be covered on that day. Such additional rounds are also contemplated in October and November, 1999. Apart from vaccination at booths, the additioal rounds will also include a house to house immunization drive for missed out children.

Increase in malaria incidents in Orissa, Bihar and West Bengal

1138. SHRI ANANTA SETHI: Will the Minister of HEALTH AND FAMILY WELFARE be pleased to state:

(a) whether Government are aware of the increasing incidents of malaria in the tribal districts of Orissa, Bihar and West Bengal;

(b) whether the death toll due to malaria in these States has been increasing; and

(c) if so, the steps taken to eradicate malaria in these States?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE (SHRI DALIT EZHILMALAI): (a) As per reports received from these States, the incidence of malaria in most of the tribal predominant districts showed a declining trend during 1998 as compared to 1997.

(b) and (c) The reports received from these States indicate that the number of deaths due to malaria remained almost static during the years 1997 and 1998.

However, the steps taken to control malaria include:—

— Early case detection and prompt treatment (EDPT);